SHRI MALLIKARJUN: He is referring to the general statement of the Cabinet Minister, not relating to the laying of the track. So, I am not supposed to give any information in general. You asked specifically about the laying of the track.

SHRI T. R. BALU: Sir, there is a metre gauge line traffic from Madras to Tuticorin. Now, we have come to understand that the Railway Department has decided to remove the M.G. line from Madurai to Tuticorin. We have also come to know that the proposed change-over to broad gauge line from Madurai to Tuticorin is being privatised.

This proposed act of removing M.G. line by Railway Department has created a lot of hue and cry and the people of Tamil Nadu are agitating for non-removal of the M.G. line traffic. In this connection I would like to request the hon. Minister to state on the floor of the House whether he will maintain *status quo* and separate broad gauge line will be provided to connect the B.G. line left out from Madurai to Tuticorin.

MR. CHAIRMAN: The question is about privatisation.

SHRI T. R. BALU: People of Tamil Nadu are agitated over this. Hon. Minister should answer this.

MR. CHAIRMAN: Your supplementary does not arise out of this question. Next Question.

Deforestation/Poaching in the Western Ghats

*3. DR. BAPU KALDATE:†
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the deforestation, shifting of cultivation and poaching in the Western Ghats threatening the flora and fauna besides causing severe depletion of the forests;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what measures have been taken by Government for preservation of wild life and for maintaining the ecological balance in the Western Ghats?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) The Western Ghats run through the States of Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamilnadu.

No case of any large scale deforestation has been reported, however, cases of smuggling of sandal-wood have come to the notice of the Central Government.

Sporadic cases of poaching of wild animals particularly elephants have been reported. Instances of sporadic cases of shifting cultivation in Maharashtra, Karnataka and Kerala have been reported.

(c) Central Government have been assisting the State Governments through a number of centrally sponsored schemes for protection of forests and wildlife. Strict enforcement measures to regulate poaching have been taken.

The Central Government have also initiated an Integrated Action Oriented Research Development and Extension scheme related to ecology of the area.

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, इस जवाब में मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं आया है और वह यह है कि आपने वननाशन की बात कही है लेकिन सवाल तो वनीकरण का है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में हाइयेस्ट ग्वालिटी पर कोयला डैम्प है और इसकी सिल्टिंग का या सिट्टी

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bapu Kaldate.

अन्दर जाने का जो अन्दाज़ किया गया था अब उससे डेढ़ गुना अधिक सिल्टिंग हो रही है। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि वहां वनीकरण कुछ नहीं हुआ है। वननाशन के मामले कम हैं, लेकिन यह दूसरे नम्बर की विस्तारिक पहाड़ियां हैं ! जो चार-पांच राज्यों में चली जाती हैं। छोटी छोटी चोरियां होती हैं, घास खाते हैं, भेड़ बकरियां चली जाती हैं वह अलग बात है, इसके लिए जो कुछ कर रहे हैं वह अलग बात है। मामला बहुत गम्भीर है। लेकिन क्या आपने समूची घाटी के वनीकरण की प्रक्रिया के बारे में कुछ विचार किया है, कुछ नियोजन किया है। इसके बारे में कुछ आपने शुरु किया है, यह मेरा पहला सवाल है।

श्री कमलनाथ : बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वृक्षारोपण की हैं। माननीय सदस्य ने खास करके प्रश्न पूछते वक्त जिक्र किया कि जो बांध हैं, जो डैम है उसमें सिल्टेशन हो रही है। यह गम्भीर मामला है। मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं। इसीलिए मेरा मंत्रालय इन योजनाओं में केचमेंट ए रिया ट्रीटमेंट प्लान जो है उसकी आवश्यकता समझते हुए यह एक शर्त रखता है ताकि वृक्षारोपण साथ साथ हो और सिल्टेशन कम हो तथा जो भी बांध हैं, जो भी डैम है, उनकी जो लाइफ है वह बड़े।

वेस्टर्न घाट फारेस्ट्री प्रोजेक्ट एक बनाया गया था, कर्नाटक स्टेट ने बनाया था जो अभी डिसकशन में है। ओवरसीज डेवलपमेंट अथारिटी यू०के० के साथ इस पर चर्चा हो रही है और दो फारेस्ट सर्किल में से एक उत्तर कनारा डिस्ट्रिक्ट आफ कर्नाटक में इसकी शुरुआत होगी। इस योजना की टोटल कीमत 105 करोड़ रुपये है और यह योजना 6 सालों के अंदर पूरी कर ली जाएगी।

डा० बापू कालदाते : मेरा सवाल था कि क्या एक समूची योजना इस घाटी के लिए बनाएंगे। पूरी घाटी आपने देखी होगी। केन्द्रीय सरकार जानती होगी कि पश्चिमी घाट के पूरे विकास की योजना में वनीकरण हो। वननाशन, चोरी छिपे पशुओं के चराने आदि के लिए कोई एक कम्प्रीहेंसिव प्लान हो क्या इस दिशा में केन्द्रीय सरकार ने कोई कदम उठाया है और इसके लिए जिन राज्यों के साथ उसकी सीमा आती है क्या उन राज्यों के साथ बातचीत करके किसी एक पांच साल या दस साल की समय सीमा में वनीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए क्या इस दिशा में आपने कुछ कदम उठाया है। अपने जवाब के अंत में आपने यह कहा है कि आपने अनुसंधान, विकास, विस्तार के लिए कई योजनाएं बनायी हैं। कई योजनाएं इज ए डिफरेंट मैटर कई योजनाएं हो सकती हैं लेकिन कम्प्रीहेंसिव प्लान इज ए डिफरेंट मैटर। एक कम्प्रीहेंसिव प्लान हो जिसके मुताबिक कई योजनाएं हो सकती हैं। मेरा सवाल यह है कि इज देयर एनी कम्प्रीहेंसिव प्लान फार डेवलपमेंट आफ वनीकरण ! बाकी जो छोटी-मोटी चीजें हैं, इनके लिए क्या कोई कम्प्रीहेंसिव प्लान आपने बनाया है। क्या इसके बारे में चर्चा हुई है ?

श्री कमलनाथ : इस पूरे वेस्टर्न घाट के लिए there is an integrated, action-oriented research and development and extension scheme. This was initiated in 1983, which looks into all aspects, not only aspects of afforestation but all aspects of ecological impact. This scheme was initiated in 1983 to provide inputs of science and technology for undertaking development planning on a sound ecological basis covering the critical watershed of the region. That is exactly the point—he was talking about the dam. Either generated is important in the specially assisted programme for ecologically sound development. The Centre for Excellence—the Ecological Science Research and Training Centre—at the Indian Institute of Science is carrying out research on ecology at the Western Ghats.

SHRI YASHWANT SINHA: We had a comprehensive plan.

SHRI KAMAL NATH: There is a comprehensive plan covering various facets of it. It is not on a ad hoc basis.

डा. बापू कालदाते: कब से शुरु हुआ ?

श्री कमलनाथ: 1983 से इसकी शुरुआत की गयी है ।

श्रीमती कमला सिन्हा: महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूं जो बारम्बार समाचार पत्रों में भी आयी है । मंत्री महोदय ने एक सनूची वन विकास की योजना के बारे में उत्तर दिया लेकिन जो इसमें सबसे इम्पारटेंट बात थी इन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वह यह है कि इन वनों में सबसे महंगी लकड़ी चन्दन की लकड़ी पायी जाती है और चन्दन की लकड़ी की बड़े पैमाने पर पोचिंग होती है और साथ ही साथ हाथी की पोचिंग होती है और टॉस्क का अवैध व्यापार होता है । क्या सरकार इसको रोकने का कोई उपाय करेगी ?

श्री कमलनाथ: सर, पिछले सैशन में ही वाईल्ड लाइफ प्रोटेक्शन (अमेंडमेंट) बिल पास हुआ था । इसमें और कड़ी सजा और कार्रवाई आसान करने का प्रबन्ध किया गया है । पोचिंग जरुर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है और सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है ।

श्रीमती कमला सिन्हा: लकड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Exploitation of Ntural Gas

*4. SHRI SARADA MOHANTY:

SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state.

(a) what is the percentage and quantum of identified natural gas reserves being exploited at preent in the country;

(b) what are the reasons for not exploiting more areas;

(c) whether any local or foreign private companies are interested in exploring and utilising such untapped and unutilised reserves, if so, what are the problems that are likely to come in the way of the utilisation; and

(d) whether it is a fact that a project involving outlay of Rs. 7500 crores for exploitation of natural gas has been sanctioned; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) In 1990-91 approximately 18 billion cu.mtr. of gas was produced, representing approximately a 2.5 per cent of the recoverable reserves. At preent, the daily production is approximately 50 million cubic metres.

(b) Exploitation of gas in various areas depends on techno-economic considerations, the availability of resources, demand downstream etc.

(c) No concrete proposal is under consideration at present.

(d) The Gas Flaring Reduction Project consists of NQP and SHG process platforms, the South Bassein to Hazira Trunk Pipeline, the expansion of the Hazira Terminal and the ICP-Heera Trunk Pipeline.

Political Solution of Punjab Problem

*5. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what steps Government are contemplating for a political solution of the Punjab problem; and

(b) what are the reasons for not implementing the Rajiv-Longowal Accord so far?